



भारतीय उच्च न्यायालयों में जमानत अपीलों में वृद्धि

प्रलिस के लिये:

भारतीय उच्च न्यायालयों में जमानत अपीलों में वृद्धि, उच्च न्यायालय डैशबोर्ड, दक्ष (DAKSH), [महामारी रोग अधिनियम, 1897](#), [दंड प्रक्रिया संहिता \(CrPC\), 1973](#)

मेन्स के लिये:

भारतीय उच्च न्यायालयों में जमानत अपीलों में वृद्धि, जमानत अपीलों

चर्चा में क्यों?

कानून और न्याय प्रणाली सुधारों पर केंद्रित थकि-टैक DAKSH के 'हाई कोर्ट डैशबोर्ड' के अनुसार, भारत के उच्च न्यायालयों में दायर जमानत अपीलों की संख्या में वर्ष 2020 के बाद वृद्धि हुई है।

- DAKSH ने 15 उच्च न्यायालयों में वर्ष 2010 से वर्ष 2021 के बीच दायर 9,27,896 जमानत मामलों का विश्लेषण किया। इन न्यायालयों ने जमानत मामलों के लिये अलग-अलग नामकरण पैटर्न का पालन किया। डेटा के विश्लेषण से उच्च न्यायालयों में जमानत से जुड़े 81 प्रकार के मामले सामने आए हैं।

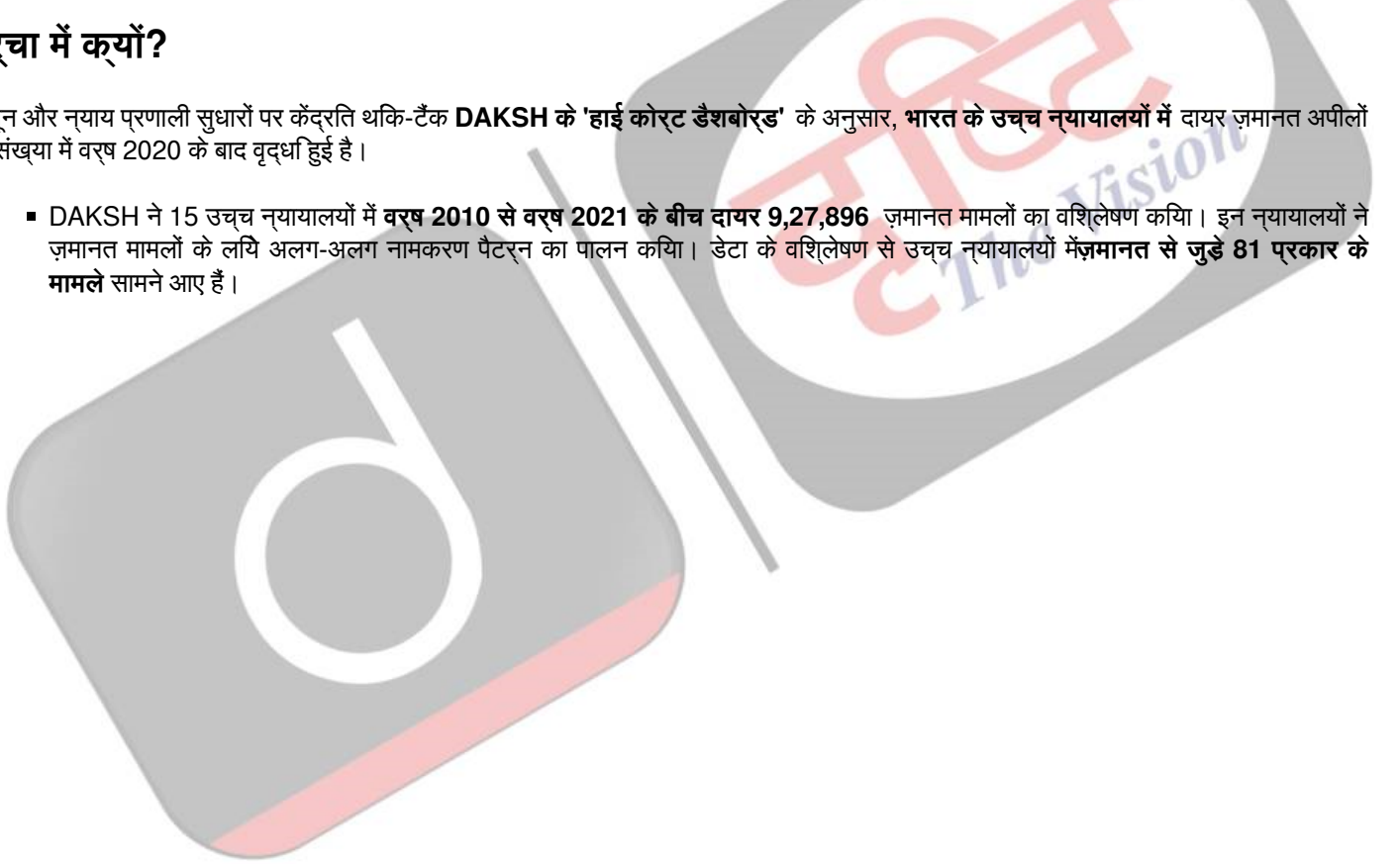


Chart 1: The chart shows the number of fresh and pending bail appeals in High Courts over time

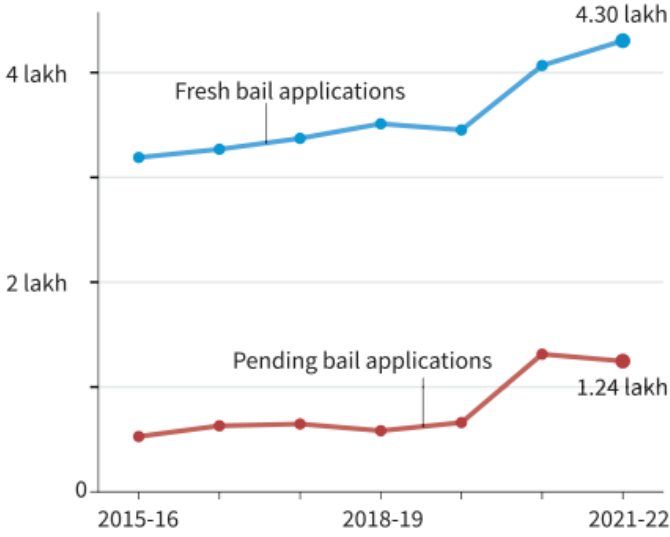


Chart 2: Bail applications filed in High courts as a share of their total caseload between July 2021 and June 2022 (in percentage)

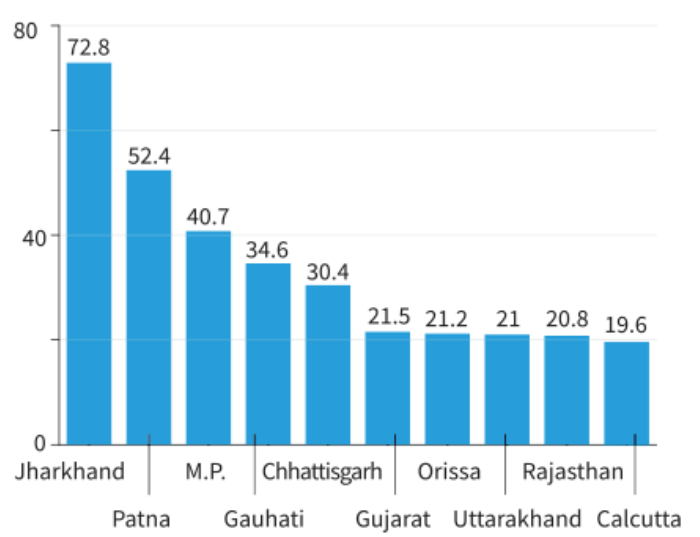


Chart 3: The chart shows the median days taken for the disposal of regular bail cases in various High Courts

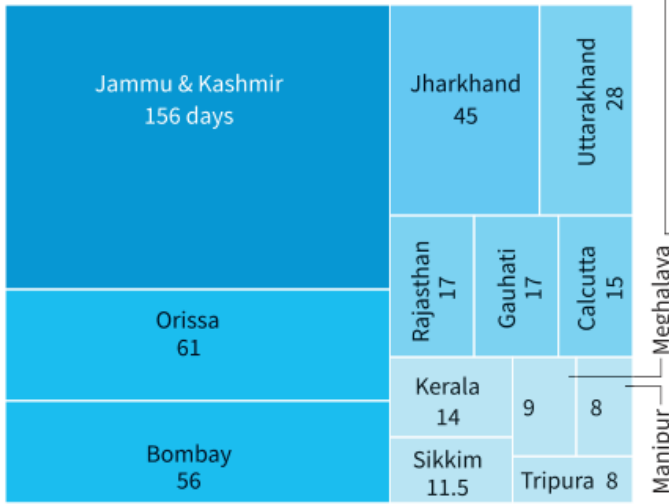
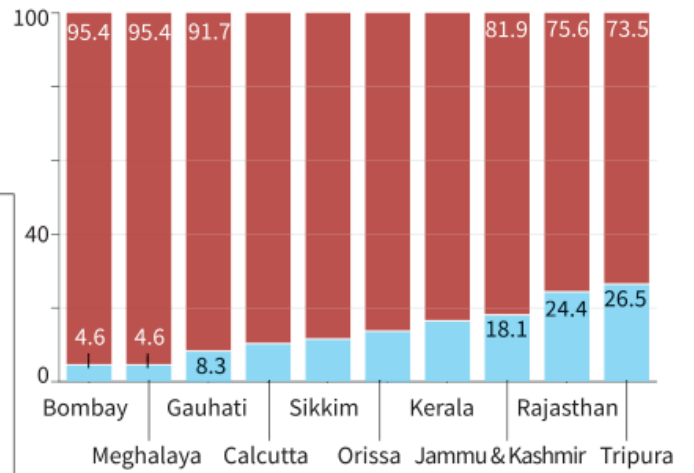


Chart 4: The chart shows the share of cases in which bail was granted/rejected and where the outcome was not given/ was unclear (in percentage)



ज़मानत अपीलों से संबंधित आँकड़े:

- **ज़मानत अपीलों में वृद्धि:**
 - वर्ष 2020 से पहले ज़मानत अपीलों लगभग 3.2 लाख से बढ़कर 3.5 लाख सालाना हो गई, उसके बाद जुलाई 2021 से जून 2022 तक 4 लाख से 4.3 लाख हो गई।
 - परणामस्वरूप उच्च न्यायालयों में लंबित ज़मानत अपीलों की संख्या लगभग 50,000-65,000 से बढ़कर 1.25 लाख से 1.3 लाख के बीच हो गई है।
- **उच्च न्यायालय और मामलों का वितरण:**
 - **वभिन्न उच्च न्यायालयों** में मामलों का वितरण अलग-अलग था। कुछ राज्यों जैसे कपिटना, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जुलाई 2021 और जून 2022 के बीच **कुल मामलों में ज़मानत अपीलों की हस्सेदारी 30% से अधिक** थी।
- **नपिटान का समय और परणाम अनश्चितता:**
 - नयिमति ज़मानत आवेदनों के नपिटान में लगने वाला औसत समय वभिन्न उच्च न्यायालयों में **भन्न है**। कुछ उच्च न्यायालयों में नपिटान का समय काफी अधिक था, जिससे **समाधान प्रक्रिया में देरी देखी गई**।
 - **ज़मानत के मामलों पर नरिणय लेने में देरी को ज़मानत को अस्वीकार करने के समान माना जाता** है, क्योंकि इस अवधि के दौरान आरोपी जेल में रहता है।
- **अपूर्ण परणाम डेटा:**

- डेटा ने उच्च न्यायालयों में जमानत अपीलों के परणामों के संबंध में स्पष्टता की कमी को भी उजागर किया। सभी उच्च न्यायालयों में नपिटाए गए लगभग 80% जमानत मामलों में, चाहे वह मंजूर हुई हो या खारज़ हो गई हो, अपील का परणाम अस्पष्ट या गायब था।

जमानत अपीलों में वृद्धि का कारण:

- **कोविड उल्लंघन और न्यायालय के कामकाज में व्यवधान:**
 - महामारी के दौरान कोविड-19 लॉकडाउन मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है।
 - इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान न्यायालयी कामकाज में व्यवधान के कारण लंबित जमानत मामलों का इस वृद्धि में योगदान हो सकता है।
 - हालाँकि न्यायालय के डेटा से निश्चिती रूप से सटीक कारण का नरिधारण नहीं किया जा सकता है।
- **महामारी रोग अधिनियम, एक कारक के रूप में:**
 - जमानत अपीलों की वृद्धि में **महामारी रोग अधिनियम, 1897** की भूमिका मानी जा सकती है। 77% नयिमति जमानत मामले ऐसे हैं जिनके वषिय में वशिष्ट अधिनियम में उल्लेख नहीं है जिसके तहत अपीलकरत्ता को कैद किया गया था, शेष 23% मामले, जनिमें वभिन्न अधिनियमों के तहत जमानत की मांग की गई उसमें **महामारी रोग अधिनियम चौथे स्थान** पर है।
 - यह इस अधिनियम के तहत मामलों में संभावति वृद्धि का संकेत देता है, जसिसे जमानत अपीलों में वृद्धि हो सकती है।

जमानत और इसके प्रकार:

- **परभाषा:**
 - जमानत कानूनी हरिसत के तहत रखे गए (उन मामलों में जनि पर न्यायालय द्वारा अभी फैसला सुनाया जाना है) व्यक्तीकी सशरत/अनंतमि रहिाई है, जो आवश्यकता पडने पर न्यायालय में उपस्थति होने का वादा करता है।
 - यह रहिाई के लयि न्यायालय के समक्ष जमा की गई सुरक्षा/संपार्श्वकि का प्रतीक है।
 - अधीक्षक और कानूनी मामलों के परामर्शदाता बनाम अमयि कुमार रॉय चौधरी (1973) मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जमानत देने के पीछे के सदिधांत को समझाया है।
- **भारत में जमानत के प्रकार:**
 - **नयिमति जमानत:** यह न्यायालय (देश के भीतर कसिी भी न्यायालय) द्वारा दयिा गया एक नरिदेश है जो पहले से ही गरिफ्तार और पुलसि हरिसत में रखे गए व्यक्तीको रहिा करने हेतु उपलब्ध है। ऐसी जमानत के लयि व्यक्ती **CrPC, 1973** की धारा 437 तथा 439 के तहत आवेदन दाखलि कर सकता है।
 - **अंतरमि जमानत:** नयिमति अथवा अग्रमि जमानत हेतु आवेदन न्यायालय के समक्ष लंबति होने की स्थतिमें यह जमानत न्यायालय द्वारा **अस्थायी और अल्प अवधि हेतु** दी जाती है।
 - **अग्रमि जमानत या पूर्व-गरिफ्तारी जमानत:** यह एक कानूनी प्रावधान है जो आरोपी व्यक्तीको गरिफ्तार होने से पहले जमानत हेतु आवेदन करने की अनुमति देता है। **दंड प्रक्रयिा संहतिा, 1973 की धारा 438** में भारत में पूर्व-गरिफ्तारी जमानत का प्रावधान कयिा गया है। इसे केवल सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दयिा जाता है।
 - अग्रमि जमानत का प्रावधान **वविकाधीन** है तथा न्यायालय अपराध की प्रकृती और गंभीरता, आरोपी के पूर्ववृत्त एवं अन्य प्रासंगकि कारकों पर वचिार करने के बाद जमानत दे सकता है।
 - न्यायालय जमानत देते समय कुछ शरतें भी लगा सकता है, जसिमें पासपोर्ट ज़ब्त करना, देश छोडने पर प्रतबिंध या पुलसि स्टेशन में नयिमति रूप से रपिरट करना आदि शामिल हैं।
 - **वैधानकि जमानत:** वैधानकि जमानत, जसि **डफिल्ट जमानत** के रूप में भी जाना जाता है, CrPC की धारा 437, 438 और 439 के तहत सामान्य प्रक्रयिा से प्राप्त जमानत से अलग है। जैसा कनिाम से स्पष्ट है, वैधानकि जमानत तब दी जाती हैजब पुलसि अथवा जाँच एजेंसी नरिदषिट समय-सीमा के भीतर अपनी रपिरट/शकियत दर्ज करने वफलि हो जाती है।

नोट: भारतीय संवधान का अनुच्छेद 21 सभी को जीवन और व्यक्तीगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह मानवीय गरमिा तथा व्यक्तीगत स्वतंत्रता के साथ जीने का मौलकि अधिकार प्रदान करता है, यह हमें कसिी भी कानून प्रवर्तन इकाई द्वारा हरिसत में लयि जाने पर जमानत प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।

स्रोत: द हद्रि